THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up Half-an-Hour Discussion.

—————————

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points arising out of the answer given in the Rajya Sabha on the 6th August, 2010 to Starred Question No. 185 regarding 'Shortage of teachers'

श्री रामविलास पासवान (बिहार) : उपसभापति जी, सरकार ने अपने मूल प्रश्न के जवाब में कहा है कि RTI Act के मुताबिक 6 साल के बच्चों के लिए 5.8 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की ज़रूरत है और 14 साल तक के बच्चों के लिए 2.44 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत है तथा इसके अलावा राज्य सैक्टर में 5.23 लाख vacancies हैं। यदि इनका टोटल आप देखें, तो 13.26 लाख vacancies हैं और जो posts sanction की गई हैं, वे हैं - 2009-10 में 2.52 लाख और 2010-11 में 1.37 लाख। बिहार के संबंध में मंत्री जी ने specifically कहा है कि बिहार में 2,60,441 posts sanctioned हैं और 1,00,696 का backlog है। एक तरफ पूरे देश में बेरोज़गारी की समस्या है और दूसरी तरफ लाखों की संख्या में यानी 13 लाख से ज्यादा posts vacant हैं। यह एक गंभीर समस्या है। शिक्षकों के वेतनमान का मामला है। अब आप शिक्षामित्र को ही ले लीजिए। आप किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, जहां बड़े-बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं, उनका एक अलग standard है, उनका एक अलग वेतनमान है और जो सरकारी स्कूल हैं, उनका एक अलग वेतनमान है। आजकल जो शिक्षामित्र की बहाली daily wages पर की जाती है, जो casual बहाली हो रही है, उसका रेट 4,000 रुपए प्रति माह है। आप समझ सकते हैं कि 4,000 रुपए प्रति माह में क्या होगा?

उपसभापति जी, मैं यह कह रहा था कि एक तरफ तो लाखों की संख्या में शिक्षकों की vacancies हैं, backlog पड़ा हुआ है और उनको भरने के लिए सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि शिक्षा का मामला स्टेट लिस्ट में आता है, हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल स्कूल वगैरह भारत सरकार के जिम्मे आते हैं। लेकिन अधिकांश राज्य सरकार का मामला है, इसलिए वे राज्य सरकार से request ही कर सकते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस संबंध में serious होकर राज्य के शिक्षा मंत्री को बुलाएंगी और इसके ऊपर तीन-चार चीजों पर निर्णय करेंगे? एक तो यह है कि जो बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहां बड़े-बड़े घर के लड़के पढ़ते हैं, उनमें 20 लाख, 25 लाख रुपए कैपिटेशन फी देकर एडमिशन होता है। जो सरकारी स्कूल्स हैं, वहां शिक्षकों को 15-20 हजार रुपए प्रति माह तनख्वाह मिलती है। अब एक नई पद्धति शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत 4 हजार रुपए प्रति माह पर शिक्षकों को casual के रूप में रखा जाता है। सर, अब आप समझ सकते हैं कि चार हजार रुपए में क्या हो सकता है? उसका कोई standard नहीं है। इस डिसकशन में दूसरे नंबर पर रूडी जी का नाम है। बिहार में कह दिया गया है कि मैट्रिक पास कोई भी लड़का आ जाओ और appointment letter लेकर चले जाओ। ...(**समय की घंटी**)... सर, यह तो Half an Hour Discussion है, कोई क्वेश्चन नहीं है।

श्री उपसभापति : हां, यह Half an Hour Discussion ही है।

श्री रामविलास पासवान : सर, कम से कम दस मिनट का समय तो दीजिए।

श्री उपसभापति : नहीं, दस मिनट का समय कैसे दे सकता हूं? देखिए, इस पर छः लोग बोलने वाले हैं, अगर प्रत्येक को दस-दस मिनट का समय दिया जाएगा, तो एक घंटा हो जाएगा और half an hour नहीं रहेगा।

श्री रामविलास पासवान : सर मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं।

श्री उपसभापति : जल्दी समाप्त कीजिए। आप क्वेश्चन पूछिए न।

श्री रामविलास पासवान : सर, चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए उस दिन चेयर ने इसको मंजूर किया था। यह सिर्फ क्वेश्चन से समाप्त नहीं होने वाला था, इसलिए उन्होंने Half an Hour Discussion मंजूर किया था। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पूरे देश में शिक्षकों के लिए एक वेतनमान तय करने का काम करेगी? आज शिक्षकों को कहीं चार हजार रुपए प्रति माह मिलता है, तो कहीं 25 हजार रुपए प्रति माह मिलता है। मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं, वहां पर एक ही स्कूल में एक शिक्षक को चार हजार रुपए प्रति माह मिलता है और दूसरे को 25 हजार रुपए प्रति माह मिलता है। जिसको चार हजार रुपए प्रति माह मिलता है, वह बच्चे को क्या पढ़ाएगा?

सर, हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में थे और 1969 में एम.एल.ए. बने थे, तो हम लोग नारा लगाते थे कि "राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान" सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। आपने प्राइवेट स्कूल में गरीब के बच्चों के लिए 25 परसेंट रिजर्वेशन कर दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या monitoring system है? क्या प्राइवेट स्कूलों में 25 परसेंट गरीब बच्चों का एडमिशन हो रहा है।

बड़े लोगों के बच्चे कार में जाते हैं और अच्छी-अच्छी ड्रेस पहन कर जाते हैं, जिसे कारण गरीब बच्चे inferiority complex से ग्रसित होते हैं और इससे वे भविष्य में गलत रास्ते पर जा सकते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ equal education से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि इसके साथ-साथ equal opportunity भी होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम 6 से 14 साल के बच्चे को समान अवसर देंगे, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि समान अवसर का मतलब होता है फ्री में खाना, फ्री में कपड़ा, फ्री में किताब, फ्री में कापी और एक तरह की ड्रेस, जिससे किसी जात का पता नहीं चले, अमीर-गरीब का पता नहीं चले। तब जाकर के बच्चों के अंदर जो inferiority complex है, वह दूर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, तो लड़के हीन भावना से ग्रसित होंगे और उनमें inferiority complex होगा तथा इससे समाज में विघटन की भावना दिनोंदिन आती जाएगी।

सर, उसी तरह से quality का मामला है। सभी जगह एक quality होनी चाहिए। एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का चपरासी बनता है और दूसरे स्कूल में पढ़ने वाला लड़का आईएएस बनता है, बड़े-बड़े पद पर जाता है, इसलिए जो quality का मामला है, उसको भी देखिए। उस दिन भी यह मामला उठा था कि शिक्षक और छात्र में क्या अनुपात होना चाहिए? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: पासवान जी, यह shortage of teacher पर है। ...(**व्यवधान**)... मैं इसको कैसे half an hour में complete करूं? ...(**व्यवधान**)... इस पर मिनिस्टर को जवाब भी देना है।

श्री रामविलास पासवान : सर, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। तमिलनाडु के एक साथी ने कहा कि पांच सौ छात्र पर सिर्फ एक शिक्षक है। या आपने पूरे देश के स्तर पर एक मानदंड बनाया है कि एक शिक्षक के अधीन कितने छात्र पढ़ेंगे? इस तरह की स्थिति लगभग पूरे देश में है।

सर, बिहार में 10+2 का मामला है। वहां 10+2 लागू कर दिया गया है और वहां हाई स्कूल्स हैं, लेकिन हाई स्कूक्स में laboratories नहीं हैं। कॉलेज से लड़के को निकाल कर कह दिया गया कि 10+2 में आओ। वहां infrastructure नहीं है। इस तरह की अनियमितताएं हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, शिक्षा मंत्री का हो या मुख्य मंत्री का हो, एक सम्मेलन बुला कर, यह जो दो तरह की शिक्षा नीति है या शिक्षकों के वेतन के बीच जो भेदभाव किया जाता है या पढ़ाई के बीच जो भेदभाव किया जाता है या opportunity के बीच जो भेदभाव किया जाता है, उनको पूरे देश में equal level पर लाने का प्रयास करेगी? आपने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाएं हैं तथा और भी क्रातिकारी कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस रफ्तार से आप यह कर रहे हैं, अगर उसी रफ्तार से गरीब और अमीर के बच्चे को एक साथ, एक बाजू पर नहीं लाएंगे, तो उसमें विषमता और फैलेगी तथा भविष्य में वे विघटनकारी तत्व की ओर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (बिहार) **:** सर, यह हमारा सौभाग्य है और रामविलास जी कह रहे हैं, वे हमारे राज्य के हैं और नेता भी हैं, लेकिन एक अजीब सी विषमता है। एक तरफ जब हम अपनी बात कहते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि कुछ लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है, वे अच्छे हैं और कुछ लोग under-privileged हैं। महोदय, अगर आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, मैं यहां बोल रहा हूं, तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में अच्छी शुरुआत हुई थी, जब हमने पढ़ाई आरंभ की थी और आज मैं इस स्थान पर खड़ा होकर इसलिए बोल पा रहा हूं कि मुझे वह शिक्षा मिली है। अगर हम किसी को नीचा समझते हैं, दूर समझते हैं, उसको उतना प्रभावशाली नहीं पाते हैं, तो स्वाभाविक तौर से उनकी यह बात ठीक है कि उसको वह opportunity नहीं मिली, लेकिन अपनी बहस में हमेशा यह लाना कि कुछ को बेहतर मिला है और कुछ को नहीं मिला और बेहतर को कम किया जाए, मैं नहीं समझता हूं रामविलास जी, इस बात पर कभी सहमति होगी कि बेहतर को कम करें। हमारा यह प्रयास है ...(**व्यवधान**)...

श्री रामविलास पासवान : हम बेहतर को कम करने की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं कह रहा हूं कि जो पीछे छूटा है, उसको हम उस स्थान तक पहुंचा दें, यह देश का उद्देश्य होना चाहिए और इसी पर हम काम कर रहे हैं। महोदय, मैं बिहार से विधायक भी रहा हूं और 22 साल पहले मैं विधायक बन गया था। मुझे याद है जब मैं अपने प्राथमिक विद्यालय में गया, तो मैं विद्यालय के एक कमरे के भीतर चला गया। वहां मास्टर साहब बैठे हुए थे। वहां आगे की पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति में बच्चे बैठे हुए थे और उनमें सब कद-काठी के बच्चे थे। सबसे पहली लाइन में कुछ छोटे-छोटे बच्चे थे, उसके बाद छोटी-छोटी लड़कियां थीं और उन लाइनों का साइज़ छोटे से लेकर बड़ा था। वह gallery की तरह था। मैंने पूछा कि ये हर उम्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो कहा गया कि विधायक जी, आप आए हैं, तो पहली तीन लाइनें जो हैं, वह क्लास 1 है, उसके बाद तीन से पांचवीं लाइन तक जो है, वह क्लास 4 है और उसके बाद सातवीं लाइन से नवीं लाइन तक जो है, वह क्लास 7 है। मास्टर साहब छड़ी लेकर बैठे हुए हैं और वे क्लास 3 को भी पढ़ा रहे हैं, क्लास 7 को भी पढ़ा रहे हैं और क्लास 9 को भी पढ़ा रहे हैं। यह इसी देश में होता है।

महोदय, आज हम लोग जिस प्रकार से भी चर्चा करें, कपिल सिब्बल साहब कुछ लिख रहे हैं, ज़रूर कुछ और लिख रहे होंगे क्योंकि उनको हर विषय का पूरा ज्ञान रहता है, लेकिन जो विषय मैं रखना चाह रहा हूं, तो बिहार से यह चर्चा शुरू हुई। हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से आपने कहा कि बिहार में लगभग सवा लाख शिक्षक हैं, मध्य विद्यालय में 1,47,000 हैं और लगभग एक लाख की vacancies हैं। बिहार तो हमारा

राज्य है, नालन्दा विश्वविद्यालय का बिल आपने पास किया, हज़ारों करोड़ मिलेंगे। आपका राज्य भी है, आप वहां के मंत्री रहे हैं, कपिल सिब्बल जी वहां से सांसद भी रहे हैं, आपका भी दायित्व है उस दिन जब यह चर्चा शुरू हुई और यह प्रश्न आज इसलिए उठा क्योंकि इसमें आपने उस दिन एक हास्य की स्थिति में बिहार की चर्चा की कि बड़ी vacancies हैं! यह दायित्व सिर्फ राज्य सरकार का नहीं है। यह बात दूसरी है कि जिस सरकार में आप हैं, उसकी सरकार इस देश में पचास वर्षों तक रही है, तो उन लाखों की vacancies में हम सबकी भागीदारी है। आज जब आप कहते हैं कि पूरे देश में शिक्षा पर हम 2,31,000 करोड़ का बजट खर्च कर रहे हैं, तो उसमें आप कहते हैं कि 68 प्रतिशत है, यानी कि आप देश के लोगों को कहना चाहते हैं कि जो 2,31,000 करोड़ खर्च हो रहा है, उसमें से लगभग पौने दौ लाख आप दे रहे हैं। शायद इस टिप्पणी में आपको संशोधन करना होगा और हो सकता है कि यह टिप्पणी सच हो, लेकिन अगर इस टिप्पणी में सुधार किया जाए, तो इस देश में...कपिल जी, आप आज इस देश के जाने-माने वकील भी हैं। सौभाग्य से आज मंत्री भी हैं, नेता भी हैं, लेकिन आपके पास जो है, आपके परिवार वालों ने आपको पढ़ाया होगा, मास्टर ने पढ़ाया होगा, आज जैसे उस कुर्सी पर जैसे उपसभाध्यक्ष बैठे हैं, आप बैठे हैं, देश में हर जगह अगर शिक्षा में वह पूंजी लगाई जाए, थोड़े दिन के लिए बाकी सब चीज़ों को छोड़ा भी जाए, लेकिन आज अगर राज्य सरकारों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, राज्य सरकारें अगर शिक्षकों का वेतन नहीं दे सकती हैं, तो मूल कारण क्या है? कोई राज्य सरकार आखिर क्यों नहीं चाहेगी कि हमारे पास पूरे शिक्षक हों? मूल कारण है कि राज्य सरकार के पास इतना दायित्व होता है कि उसको गरीबों का पेट भी भरना है, उसको सड़क का निर्माण भी करना है, उसे डैम का निर्माण भी करना है और सारा खज़ाना लेकर आप दिल्ली में बैठे हैं! राज्यों का तो यही कहना है। अगर आप पैसा दे दें... आपने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। सर्व शिक्षा अभियान सफल अभियान रहा। जहां-जहां आपने भेजा, नियुक्तियां हुईं, टीचर्स आए, यह बात दूसरी है कि 2007 में देश के प्रधान मंत्री, पिछले 6 वर्षों की तरह, लाल किले पर भाषण देकर आए। उन्होंने कहा था कि लगभग 5000 ऐसे विद्यालय बनाएंगे, जिनमें हर जिले में एक ऐसा विद्यालय होगा, जो प्रामाणिकता से स्थापित करेगा कि प्राथमिक शिक्षा, मध्य शिक्षा इस देश में किस प्रकार की हुई।

उस गुणवत्ता को स्थापित करने के लिए हम लोग पांच हजार विद्यालय बनाएंगे। प्रधान मंत्री जी की जो cut and paste speech होती रहती है - पिछले साल का काटकर इस साल लगा देते हैं, इस साल का काट कर उस साल लगा देते हैं - कम से कम मंत्री जी उनकी स्पीच को निकालकर, पढ़कर जो प्रधान मंत्री जी इस देश में बोलें, उसको तो पूरा करा दिया कीजिए। कभी-कभी उसको ही पढ़ लिया कीजिए क्योंकि cut and paste से हम भी परेशान है।

श्री उपसभापति : आप इस तरह से मत बोलिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, मैं उसको छोड़ देता हूं क्योंकि वह कठिन होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not correct. That was an Address to the Nation.

श्री राजीव प्रताप रूडी : प्रधान मंत्री जी का जवाब देने के लिए, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल भी बीच में आ जाएगा। मैं इसे समझ सकता हूं। ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि ...(**व्यवधान**)... अजय जी, आपका विभाग दूसरा है, आप चिदम्बरम जी के विभाग में हैं। ...(**व्यवधान**)...

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अजय माकन**) : मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं सही बोल रहा हूं।

श्री अजय माकन : लेकिन आप इधर से उधर चले जाते हैं। आप विषय पर बोलिए न।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं सही बोलता हूं और हमेशा अच्छा बोलता हूं, लेकिन जगाने के लिए कभी-कभी झंझोड़ना पड़ता है। ...(**व्यवधान**)... क्योंकि हम लोग उस ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि यहां पर जो भी आपका प्रयास है, बिहार को आप विशेष रूप से देखें। बिहार इस देश की धरोहर है, वहां से आज हमारे जैसे तमाम लोग आते हैं। हम जानते हैं कि बिहार का हुनर पूरे देश और दुनिया में देखने को मिलता है। हमारा भी प्रयास रहता है कि वहां के नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले। हो सकता है कि राज्य के पास पैसा नहीं है - बहुत से राज्यों के पास पैसा नहीं है, लेकिन उपहास करने से अच्छा होगा कि उस राज्य को आप पैसा दें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सर्व शिक्षा अभियान आपका अच्छा अभियान था। इसी प्रकार से आप राज्य सरकार को मदद करें, लेकिन राज्य सरकार को केन्द्र सरकार उपहास की स्थिति में न छोड़ करके उसके संबंध में कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसी पहल करे जिससे, देश और दुनिया में प्रधान मंत्री जी जो नौ फीसदी ग्रोथ की बात करते हैं, हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप और पूंजी निवेश करें, तो वह नौ प्रतिशत बारह प्रतिशत बन जाए। इसलिए एक इंसान की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अगर केन्द्र सरकार सहयोग करे तो मैं समझता हूं कि शिक्षकों की नियुक्ति उसकी प्रारंभिक कड़ी होगी और उस प्रारंभिक कड़ी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार की भूमिका राज्य सरकार से अधिक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से कहूंगा कि सब चीज़ें अगर कुछ दिनों के लिए छोड़नी भी पड़ें, जो उचित नहीं लगता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप उन्हें खड़ा कर देंगे तो इस देश में बहुत से राजीव प्रताप रूडी, अरुण जेटली और कपिल सिब्बल खड़े हो जाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : सर, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ये जो शिक्षक appoint करेंगे, उनके संबंध में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि North India में जितनी स्टेट्स हैं, वहां छठी क्लास से इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं। उससे उस बच्चे की जो ग्रोथ है, उसमें आगे चलकर बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए शुरू से, क्लास-वन से, elementary level से उसके लिए इंग्लिश की शिक्षा की व्यवस्था करें और अगर इसके लिए टीचर्स नहीं मिलते हैं तो South India से टीचर्स लाएं। इससे कल्चर मिलेगा। एक-एक गांव में अगर South India का टीचर होगा तो दोनों तरफ का कल्चर मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा।

श्री उपसभापति : राजीव शुक्ल जी, आप अपनी सीट से बोलिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी।

श्री राजीव शुक्ल : इसलिए North India में प्राइमरी स्कूलों में क्लास-वन से इंग्लिश होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा inferiority complex में रहता है। यह मेरा सुझाव है जो मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। धन्यवाद।

DR. PRABHA THAKUR (Rajasthan): Sir, I associate myself with it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we have already taken 15 minutes. Only 15 minutes are left. The two main Members who had given the notice have spoken. There are five or six more requests. So, put your questions only. I will not allow any debate on this.

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब) : धन्यवाद उपसभापति जी, मैं आपे माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां पर तीन तरह के स्कूल हैं - गवर्नमेंट स्कूल, एडिड स्कूल और प्राइवेट स्कूल। बहुत से टीचर्स बीएड, जे.बी.टी., ई.टी.टी. और physical education के टीचर्स हैं। आपका यह कहना है कि टीचर्स मिलते नहीं हैं। शायद यह तथ्य गलत है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बीएड, जे.बी.टी., ई.टी.टी. करके घूम रहे हैं। अभी हमारी सरकार ने पंजाब में काफी सारी vacancies को भरा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टीचर्स unemployed हैं वे आज पानी की टंकी के ऊपर खड़े होकर आत्महत्या करने की धमकी सरकार को दे रहे हैं। सरकार ने वहां कानून बनाया है कि अगर कोई धमकी देगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। अगर ऐसी स्थिति है तो shortage कहां है, unemployment है। आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जो वन-टीचर स्कूल हैं, कई स्कूल्स नो-टीचर स्कूल हैं। जो वन-टीचर स्कूल हैं, वहां पर टीचर peon का काम भी करते हैं और क्लर्क का काम भी करते हैं। वे बच्चों को proper way से education नहीं दे पाते। इसलिए मेरा मानना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक स्कूलों में टीचर्स नहीं होंगे, dropout बढ़ेगा और dropout बढ़ेगा तो जो आप Right to Education Act लाए हैं, वह भी फेल हो जाएगा। सो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से रूडी साहब ने भी कहा है कि क्या आप राज्यों के साथ यह रेस्पांसिबिलिटी शेयर करोगे कि अगर वे जितने भी टीचर्स भर्ती करें, क्या आप टीचर्स को भर्ती करने के लिए वह पूरा फंड राज्यों को प्रोवाइड करेंगे या नहीं? जैसा आपने कहा कि शॉर्टेज है, हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी है इसलिए टीचर्स नहीं आ रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : सर, मैं भी एक क्वेश्चन करुंगा?

श्री उपसभापति : नहीं, बिल्कुल नहीं, पासवान जी ने पूरा बिहार का टाइम ले लिया है। अगर आप ऐसा करेंगे, then how will we regulate it? ...(**व्यवधान**)... आपके नेता हैं, उनसे बात करिए।

DR. N. JANARDHANA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak in this august House about the teachers. I have been a trained teacher myself. So, I am proud of that, particularly, when I speak in this House for a few minutes about teachers.

Sir, at the time when I was studying in a rural school, my teacher used to write on the wall regularly, "मात्री देवो भवः, पित्रो देवो भवः आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः"

So, you can understand that the place of a teacher is equal to the father and mother. Similarly, in every place, teacher is respected. It is still going on. The teacher is still respected in a rural area, but not in an urban area where they don't treat him well.

Sir, teacher is an important input for education.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please ask the questions on shortage of teachers. The discussion is on shortage of teachers.

DR. N. JANARDHANA REDDY: Sir, I am coming to that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please seek clarifications from the hon. Minister on shortage of teachers.

DR. N. JANARDHANA REDDY: He also told that the shortage is there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But we are not discussing the importance of a teacher. We are not discussing that.

DR. N. JANARDHANA REDDY: Sir, I am talking about the importance of teachers and the training of teachers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Even we are not discussing all that. This discussion is not on those things.

DR. N. JANARDHANA REDDY: Even if you permit me to ask a question on it, it will be related to that only.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The reason why I am saying it is because the purpose of this Half-an-Hour Discussion will be lost in this manner. You have to elicit information on shortage of teachers. That is why this Half-an-Hour Discussion has been taking place.

SHRI RUDRA NARAYAN PANY (Orissa) : Sir, there is shortage of textbooks also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, it is not on textbooks also. You can discuss anything on education under a Short Duration Discussion.

DR. N. JANARDHANA REDDY: When a teacher enters the class, you weigh him. You weigh him before he enters the class. When he goes out of the class, you again weigh him. But his knowledge-weight should be more. The teacher has also to make the class learn. Sir, I don't want to take much of your time. In our country, teachers are being trained. But some of them have started their own schools and they are running them. I think, the Government of India has to help the State Government.

So, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to speak about the teachers which is an important issue but not being attempted adequately. We have to help them. I don't think our hon. Minister, Kapil Sibalji, is a trained teacher.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is a trained lawyer.

DR. N. JANARDHANA REDDY: But he is taking education in the right direction. We can help him. Thank you.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : धन्यवाद सर। मैं खड़ा होकर ही जल्दी बैठने वाला हूं। मैं केवल इतनी ही बात पूछना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान में आपने बहुत पैसा बिहार को दिया है। ये लोग सर्व शिक्षा अभियान का पैसा ही बिहार में खा गए। उसका क्या होगा? यह अलग बात है। सर, मेरा प्वाइंटिड क्वेश्चन है। क्या शिक्षकों की बहाली आप जल्दी से करने वाले हैं? क्या आप पूरे देश में शिक्षा में समानरूपता लायेंगे? जैसे "A" से Apple होता है, चाहे उसको बिहार में पढ़ाइए, चाहे उसको कर्नाटक में पढ़ाइए। मंत्री जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई ऐसी पॉलिसी बनायेंगे, ताकि शिक्षकों की जब बहाली हो, तो उनका मान हो, मर्यादा हो और उनको अच्छी तनख्वाह मिले? उनको चार हजार वाली तनख्वाह नहीं, उनको चार हजार-पांच हजार वाली तनख्वाह नहीं, उनको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए। आप बहुत प्रगतिशील आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे प्वाइंटिड क्वेश्चन पूछ रहा हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, यह कह रहे हैं कि खा गए। खा गए से मतलब क्या है? जिस तरह से ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : सर, मुझे भी सवाल पूछना है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (ASSAM): Sir, I would like to. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं। आपने नाम नहीं दिया। ...(**व्यवधान**)... श्री कुमार दीपक दास जी, आप कुछ रेस्ट लीजिए। You want to say something on every issue. Take some rest! ...*(Interruptions)*... प्रो. अनिल कुमार साहनी जी।...(**व्यवधान**)...

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir, in my State of Assam, Science and Mathematics teachers are less in number and they ask teachers from the Arts stream to teach the students. Now, they cannot teach students Science subjects. I want an assurance from the hon. Minister that the vacant posts of Science teachers would be immediately filled up. Also, those schools which have not been provincialised by the States should be provincialised by the State Government with the assistance of the Central Government. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, let me tell you that Notice is given to all of you; agenda is included. You don't give names earlier. आप बैठे-बैठे हाथ उठा देते हैं और लिखकर नाम नहीं देते, How do we regulate? आप मुझे सजेस्ट कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : सर, चेयर को हमने अधिकार दे रखा है। ...(**व्यवधान**)... चेयर को अधिकार और संरक्षण दोनों हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : अधिकार में टाइम को भी रेग्युलेट करना पड़ता है। आप इस बात को मानते हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : सर, एक मिनट का समय और जुड़ जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइए। प्लीज आप बैठ जाइए। आपने पहले नाम नहीं दिया। ...*(Interruptions)*... There is a procedure that names of Members should be given half-an-hour before their participation in any discussion.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir, I only want an assurance from the hon. Minister that those schools, which have not been provincialised by the State, would be provincialised with the assistance of the Central Government.

श्री उपसभापति : प्रो. अनिल कुमार साहनी। आप केवल सवाल पूछिए ...(**व्यवधान**)...

प्रो. अनिल कुमार साहनी (बिहार) : सर, मैं सवाल ही पूछना चाहता हूं। बिहार के संबंध में हमारे साथी रामविलास पासवान जी, राजीव प्रताप रूडी जी और राजनीति प्रसाद जी बोले कि सब खा गये। खा कौन गया? जो खाता है, उसी को याद पड़ता है कि खा गया है। सर, हम लोग वहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए जो काम चला रहे हैं, शिक्षा मित्र को चार हजार रुपये देकर काम चला रहे हैं, उसके लिए केन्द्र सरकार या सहायता दे रही है? वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने साइकिल दी है, पोशाक दी है, वहां के लोगों को क्रांति की ओर जाने से नीतीश कुमार ने रोका है। नीतीश कुमार ने वहां पर जमीन के लोगों को पढ़ाने के लिए कार्य किया है...।

श्री उपसभापति : आप शिक्षकों की शार्टेज़ के बारे में सवाल कीजिए।

प्रो. अनिल कुमार साहनी : सर, मेरा क्वेश्चन ही है। केन्द्र सरकार वहां के लिए क्या दे रही है, जो बोलते हैं कि खा गए, कहां से खा गए ? ...(**समय की घंटी**)... आप सवाल पर सवाल करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, मेहरबानी से ...(**व्यवधान**)... अनिल कुमार जी, यह सवाल शिक्षकों की शार्टेज़ के बारे में है। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. अनिल कुमार साहनी : वहां पर बच्चे साइकिल चलाते हैं, बच्चे-बच्चियां पोशाक पहनकर जाते हैं। आप बिहार में जाकर देखिए कि साढ़े चार साल में कितना बदलाव हुआ है? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : हो गया, हो गया। ...(**व्यवधान**)... No, I will not allow this. आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... अनिल कुमार जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... मैं आपको शिक्षकों की शार्टेज के ऊपर ही प्रश्न पूछने के लिए अलाऊ करूंगा ...(**व्यवधान**)... डा. प्रभा ठाकुर। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. अनिल कुमार साहनी : आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, हम बिहार में सारा काम पूरा करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : ठीक है, ठीक है। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. अनिल कुमार साहनी : चाहे वह काम शिक्षा के क्षेत्र का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, हम पूरा करेंगे। हम शिक्षा के माध्यम से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं।

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) **:** महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से केवल एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि सर्वशिक्षा अभियान ...(**व्यवधान**)... के तहत केन्द्र सरकार ने किस-किस राज्य को कितना-कितना धन दिया है, आर्थिक सहयोग दिया है और उसके बावजूद कौन-कौन सी स्टेट्स में शिक्षकों की पूरी भर्ती क्यों नहीं हुई है, शिक्षकों की कमी क्यों है? एक तरफ तो हम शिक्षा की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, सरकार सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील जैसी योजनाएं चलाती है ...(**समय की घंटी**)... तो क्या कारण है? पढ़े-लिखो की कोई कमी नहीं है। यह कभी न बिहार में है, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप केवल एक ही सवाल पूछ लीजिए।

डा. प्रभा ठाकुर : न उत्तर प्रदेश में है, न राजस्थान में है और न ही अन्य कहीं? क्या कारण है कि शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, कृपया यह बताएं?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... एजुकेशन टू ऑल, आप जो बिल ला रहे हैं, उसमें आपने लिखा है कि हम राज्यों को चार साल में इतने-इतने परसेंट देंगे और शेष पैसा राज्य सरकार लगाएगी, जिसमें इन्होंने हर साल रुपए कम करने के लिए लिखा है। जहां तक मेरी नॉलेज है, उसके अनुसार राज्य सरकारों ने शिक्षा मंत्री को जो आपने सुझाव दिए हैं, उनमें कहा है कि 90 परसेंट एजुकेशन पर खर्चा अगर केन्द्र सरकार से मिले, तो दस परसेंट राज्य सरकार दे, इस तरह वे सबको एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, कृपया यह बता दें कि इस पर क्या निर्णय लिया है, अगर नहीं लिया है, तो कब तक निर्णय लेंगे?

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : देखिए, राम कृपाल यादव जी, आपकी पार्टी से ...(**व्यवधान**)... मैंने हर पार्टी से एक-एक सदस्य को बोलने का मौका दे दिया है। ...(**व्यवधान**)... आप नेक्स्ट टाइम ले लीजिए। ...(**व्यवधान**)... पुराने संबंध तो सभी के हैं।...(**व्यवधान**)... मैं आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को उठाया है। यह सवाल केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है। हिन्दुस्तान में ऐसे कई प्रदेश हैं, जहां पर टीचर्स की बहुत बड़ी

कमी है। जिस दिन यह सवाल उठा था, एक माननीय सदस्य ने सवाल पूछा, तो मैंने उदाहरण के तौर पर बिहार का जिक्र किया था। यदि मुझे मालूम होता कि मेरे दोस्त व माननीय सदस्य रूडी साहब, इतना बढ़ा-चढ़ाकर बोलेंगे कि मैंने बिहार को अपमानित किया है, तो मैं कभी बिहार का उदाहरण देता ही नहीं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामविलास पासवान : बिहार का ही उदाहरण है? ...(**व्यवधान**)...

श्री कपिल सिब्बल : कई और ऐसे राज्य है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राम कृपाल यादव : आप सच्चाई तो बताओ। ...(**व्यवधान**)...

श्री कपिल सिब्बल : देखिए, इस बारे में ...(**व्यवधान**)...

श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल) **:** सारा बिहार दिल्ली में आ गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : कहने का मतलब यह है कि यह जो टीचर्स की कमी की समस्या है, यह किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, दूसरा यह कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। अगर हम राजनीति के गुंजल में फंस जाएंगे, तो हमें जितना उस राष्ट्रीय समस्या पर ध्यान देना चाहिए, उतना नहीं दे पाएंगे। डिबेट यह होनी चाहिए कि इसको किस तरह से पूरा किया जाए। मैं यहां पर बिहार की बात करता हूं, क्योंकि बिहार के ऊपर सवाल है। मैं आपको 2009 और 2010 की स्थिति बताना चाहता हूं। जो No. of Posts बिहार में सैंक्शन्ड हैं, वे 260841 हैं तथा उनमें से जो टीचर्स अपाइंट हुए हैं, वे 160145 हैं तथा आज के दिन जो कमी है, वह 100696 है। ...(**व्यवधान**)... लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने केवल आंकड़े आपके सामने रखे हैं। जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे बात-चीत की है। हमने बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया और जब उनसे वैयक्तिक तौर पर बात-चीत की तो यह बात जानकारी में आई कि यह जो 100696 की कमी है, वे इस कमी को तुरंत ही पूरा करने जा रहे हैं।

उन्होंने हमें यह बताया कि लगभग 52 हजार पोस्ट्स जल्द से जल्द फिल अप हो जाएंगी। ...(**व्यवधान**)... मैं स्थिति बता रहा हूं। अब इसमें राजीव प्रताप रुडी जी कहेंगे कि मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूं। उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और हमने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जो बाकी 41 हजार वेकेंट पोस्ट्स हैं, वे भी जल्द से जल्द फिल हो जाएंगी, क्योंकि हेड मास्टर और ट्रेंड ग्रेज्युएट टीचर्स की अपर प्राइमरी में पोस्ट्स हैं। ये नॉर्मली प्रमोशन द्वारा फिल होती हैं, इसलिए ये भी फिल हो जाएंगी। मतलब यह है कि बिहार तेजी से कोशिश कर रहा है कि पोस्ट्स फिल हो जाएं। मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने आकर मुझे यह आश्वासन दिया, लेकिन जो जमीनी स्थिति है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। न तो मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं, न ही कह रहा हूं कि यह स्थिति जल्द ही ठीक हो जाएगी। जहां यह कमी है, उसके लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए, बिहार सरकार को करना चाहिए, झारखंड सरकार को करना चाहिए, उड़ीसा सरकार को करना चाहिए, वेस्ट बंगाल को करना चाहिए, असम को करना चाहिए, छत्तीसगढ़ को करना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस जवाब के संदर्भ में आपको अपना रिएक्शन देना चाहिए था। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : मंत्री जी ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप बैठिए, अभी उन्होंने पूरा नहीं किया है। ...(**व्यवधान**)... आप बीच में इंटरफियर कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : मंत्री जी, जिन राज्यों में कमी नहीं है, उनका नाम बता दें।...(**व्यवधान**)...

श्री कपिल सिब्बल : मैंने बता दिए है, जिनमें कमी है, बाकी राज्यों में कमी नहीं है।

श्री कुमार दीपक दास : सर, नॉर्थ-ईस्ट में है, असम में है।

श्री कपिल सिब्बल : असम का नाम मैंने ले लिया है, आप दोहरवाना चाहते हो, तो मैं दोहरा देता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : यह क्या है? ...(**व्यवधान**)... This is too much. ...*(Interruptions)*...

डा. प्रभा ठाकुर : सर, इन्होंने जो बैक लॉग नहीं भरा है, उसका भी पुछवा दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : उन्होंने अभी अपना भाषण कंपलीट नहीं किया है।

श्री कपिल सिब्बल : दूसरा सवाल यहां पर उठा कि यूनिफॉर्म एजुकेशन होनी चाहिए। जब तक यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि हम यही कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन को लागू करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास इतने साधन तो हैं नहीं कि इतना पैसा इन्वेस्ट कर दें कि सभी को एक उच्च स्तर की यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। आप खुद यह कह रहे हैं कि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। अभी नरेश अग्रवाल साहब जी ने कहा, कुछ और माननीय सदस्यों ने कहा कि जब तक हमें नब्बे प्रतिशत नहीं मिलेगा, तब तक हम शिक्षा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब आप खुद कह रहे हैं कि आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप लोगों को उच्च स्तर की यूनिफार्म क्वालिटी एजुकेशन कैसे देंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा राज्य सरकारों को दे और इसीलिए अगले पांच सालों में हम इस पर 2,31,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसमें से जो 24,000 करोड़ है, वह फाइनेंस कमीशन ने केवल प्रदेशों के लिए अलग से रखे हैं। फाइनेंस कमीशन ने यह भी बताया है कि हर प्रदेश को एक साल में कितना मिलेगा। बाकी का जो 2,04,000 करोड़ है, उसका जो डिस्ट्रिब्यूशन होगा, वह 35% और 65% होगा। मैंने यह बात उस दिन भी आपके सामने रखी थी कि ओवर ऑल जो डिस्ट्रिब्यूशन तय करना है, वह 68% और 32% है। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जहां कमी है, हम उसको कोशिश करके पूरा करें, लेकिन हमारी भी कुछ पाबंदियां है, हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम सारा पैसा, हंड्रड परसेंट आपको दे दें, क्योंकि यह तो केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय तय करता है कि कितना जा सकता है और कितना नहीं जा सकता है। और भी ऐसी कई पाबंदिया केंद्र सरकार पर होती हैं। तीसरी बात, माननीय सदस्य ने यहां पर रखी कि बिहार में जो टीचर्स सैलरी है, वह छह हजार या पांच हजार रहती है। यह एक कांट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है। यह बात सही है, कई राज्यों में ऐसा हुआ। वहां अध्यापक को रेग्युलर सैलरी नहीं दे पाते थे, क्योंकि इतने साधन नहीं थे। लोग या तो प्रचारक को सैलरी देते थे या कांट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट देते थे। लेकिन बिहार की अच्छी स्थिति यह है कि बिहार में ये जो टीचर्स अपॉइंट हुए है, वे ट्रेंड टीचर्स हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री रामविलास पासवान : नहीं, देखिए आप बिहार को बचाइए मत, आप सरकार को मत बचाइए। वहां कोई ट्रेंड टीचर्स नहीं है। रूडी जी, बताइए क्या वहां पर कोई ट्रेंड टीचर है? ...(**व्यवधान**)... वहां कोई ट्रेंड टीचर नहीं है। ...(**व्यवधान**)... कोई यहां बात दे...(**व्यवधान**)... बिहार के सदस्य हैं...(**व्यवधान**)... कोई बात दे...(**व्यवधान**)... बताइए रूडी जी ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : बैठिए ...(**व्यवधान**)...

श्री रामविलास पासवान : क्या बिहार में सब trained teachers हैं? ...(**व्यवधान**)... सब untrained हैं, एक भी trained नहीं हैं। सब मुखिया के द्वारा बहाल होते हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : ठीक है।...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, इन्होंने भी ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Is it a Half-an-Hour Discussion or a Short Duration Discussion? Half-an-hour is over. Now, under the rules, I am bound to close it because it has been more than half an hour.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir he has called my name. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is all right. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, he talked about some trained teachers. ...*(Interruptions)*... He talked about some trained teachers. If I recall, his new friend, Lalu Prasad*ji* had some *charwaha vidyalaya* ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Please. ...*(Interruptions)*... I think, the half-an-hour discussion has to be ...*(Interruptions)*...

श्री कपिल सिब्बल : सर, जो वास्तविक स्थिति है, मैं सदन में रखूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री राम कृपाल यादव : सर, वहां ऐसे teachers हैं, जिनको क, ख, ग, घ नहीं मालूम है, जिनको a, b, c, d नहीं मालूम है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister, you just give some figures and sum it up because they are not interested in listening. ...*(Interruptions)*... It becomes a debate. ...*(Interruptions)*... They are not interested in listening. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Yes, they are not interested. So, there is nothing I can do. But, I just want to inform you that the Bihar Government has informed us that they recruit their teachers under the Elementary Teacher Recruitment and Service Regulations Rules 2006. ...*(Interruptions)*... This is the information given by the Bihar Government. If it is wrong, that is a separate issue. Therefore, they are recruiting their teachers under these rules. There are many States who don't recruit their teachers under any regulation. So, that is the difference between Bihar and some other States. But let me tell you ...*(Interruptions)*... Let me tell you another important thing and that is when you come to national parameters, Bihar, unfortunately, is far below the national average, in every respect. So, whereas Bihar should be congratulated for making efforts, Bihar should also know that they are far behind most of the States. ...*(Interruptions)*... Therefore, effective efforts need to be taken to make Bihar come up to the same standards. ...*(Interruptions)*...

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: This is only because of regional disparities.

SHRI KAPIL SIBAL: I am telling you the factual position. I am not giving the reasons for that position. Pupil-teacher ratio in Bihar is far below the national average. Number of class rooms is far below the national average. Levels of literacy are far below the national average. Levels of female literacy are far below the national average. That is the reality. But, Bihar, in the recent years, has also made progress. They are trying to make progress, and for that we must accept the efforts that are being made.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Short Duration Discussion on Internal Security will be taken up tomorrow after discussing with the Government. The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at fifty-three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 26th August 2010.